भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4934

उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी

†4934. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्कूलों की कुल संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में छात्रों के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के प्रशासन के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल लागू करता है।

वर्तमान में, संपूर्ण भारत में, 9,33,987 (63.5%) स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है। यूडाइज+ वित्त वर्ष 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट कनेक्शन वाले ग्रामीण स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची अनुलग्नक में दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल सामग्री के प्रसार को सक्षम बनाती है। यह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेटिक टेक्स्टबुक (ईटीबी) प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है।यह छात्रों और शिक्षकों को ई-लर्निंग, शिक्षक प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा, शहरी-ग्रामीण शिक्षा और एआई जैसे नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेपों तक पहुंच प्राप्त करने में भी मदद करता है। विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी इन डिजिटल कार्यक्रमों की प्रभावी पहुंच के लिए मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है।

भारत सरकार ने बजट 2025 में बीएसएनएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

*****

अनुलग्नक

"ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री दीपक अधिकारी (देव) द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4934 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूडाइज+ के अनुसार इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्कूल	इंटरनेट सुविधा उपलब्ध स्कूल	इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत
	भारत	**14,71,473**	9,33,987	63.5%
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	408	264	64.7%
2	आंध्र प्रदेश	61,317	60,731	99.0%
3	अरुणाचल प्रदेश	3,229	1,086	33.6%
4	असम	55,283	48,201	87.2%
5	बिहार	94,339	80,035	84.8%
6	चंडीगढ़	207	207	100.0%
7	छत्तीसगढ	56,802	36,511	64.3%
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	433	431	99.5%
9	दिल्ली	5,556	5,556	100.0%
10	गोवा	1,479	1,379	93.2%
11	गुजरात	53,355	51,514	96.5%
12	हरियाणा	23,494	18,539	78.9%
13	हिमाचल प्रदेश	17,330	11,011	63.5%
14	जम्मू और कश्मीर	24,192	11,883	49.1%
15	झारखंड	44,376	25,715	57.9%
16	कर्नाटक	74,859	37,921	50.7%
17	केरल	15,757	14,442	91.7%
18	लद्दाख	961	488	50.8%
19	लक्षद्वीप	36	36	100.0%
20	मध्य प्रदेश	1,22,120	55,865	45.7%

21	महाराष्ट्र	1,08,250	78,084	72.1%
22	मणिपुर	4,666	1,709	36.6%
23	मेघालय	14,587	3,858	26.4%
24	मिजोरम	3,974	2,580	64.9%
25	नागालैंड	2,750	1,622	59.0%
26	ओडिशा	61,565	51,588	83.8%
27	पुदुचेरी	763	760	99.6%
28	पंजाब	27,281	24,249	88.9%
29	राजस्थान	1,06,302	74,358	69.9%
30	सिक्किम	1,245	643	51.6%
31	तमिलनाडु	57,935	49,211	84.9%
32	तेलंगाना	43,154	27,309	63.3%
33	त्रिपुरा	4,943	2,059	41.7%
34	उत्तर प्रदेश	2,62,358	1,20,465	45.9%
35	उत्तराखंड	22,452	16,236	72.3%
36	पश्चिम बंगाल	93,715	17,441	18.6%